

INDIAN HISTORY CONGRESS
(Established, 1935)

Prof. Syed Ali Nadeem Rezavi
Secretary

Date: 03/09/2026



4/735
Taj Mansion, Friends Colony
Dodhpur Area
Aligarh – 202001
Email: ihc.secretary23@gmail.com

URGENT ANNOUNCEMENT

It is now evident that, due to the obstructive stance and persistent non-cooperation of Mr Ramesh B., Vice-Chancellor of Dr Manmohan Singh Bengaluru City University, it will not be feasible to hold the December Session of the Indian History Congress (IHC) at the University.

Although the Vice-Chancellor had initially consented to host the Session, he has now unequivocally refused to undertake the responsibilities indispensable for its organisation. He has declined to apply to the Government of Karnataka for the necessary financial grant, maintaining instead that the IHC should itself arrange the required funds. According to his position, the University would do no more than provide the venue.

He has also refused to appoint a Local Secretary, citing the University's limited permanent staff and their already heavy existing burdens. In these circumstances, there would effectively be no local institutional machinery available to organise a Session attended by nearly a thousand delegates.

What is particularly regrettable is that this final position was communicated to us only after the matter had been allowed to remain pending for almost four months. During this period, our repeated letters, messages, and requests elicited no substantive response, while we continued to proceed in good faith on the assumption that the University's earlier commitment to host remained valid.

When we specifically asked the Vice-Chancellor why, if the University was unable or unwilling to assume responsibility, he had allowed the matter to remain unresolved for so long, his explanation was telling. He stated that when he initially agreed, he had assumed that the IHC Session was akin to other academic conferences attended by perhaps 100 to 150 participants, who typically meet their own expenses. He subsequently realised that an IHC Session is an altogether different undertaking, involving a very large number of delegates and requiring substantial organisational and financial support. Unfortunately, this misunderstanding was never communicated to us, despite our persistent attempts over several months to clarify precisely these requirements. Had the University informed us at the outset that it was unwilling to seek financial assistance, appoint a Local Secretary, or assume organisational responsibility, we would have had ample time to explore alternative venues.

As a consequence, with barely four months remaining before the scheduled December Session, the Indian History Congress has been placed in an extraordinarily difficult predicament through no fault of its own. We therefore have no alternative but to withdraw from the proposed arrangement with Dr Manmohan Singh Bengaluru City University and to urgently initiate efforts to secure an alternative venue for the forthcoming Session.



जरूरी घोषणा

यह अब साफ हो गया है कि डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री रमेश बी. के रुकावट पैदा करने वाले रवैये और लगातार गैर-सहयोग की वजह से, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस (IHC) का दिसंबर सत्र इस यूनिवर्सिटी में आयोजित करना संभव नहीं हो पाएगा।

हालाँकि कुलपति जी पहले इस सत्र के आयोजन के लिए राजी हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कर्नाटक सरकार से आर्थिक सहायता (अनुदान) माँगने से इनकार कर दिया है और कहा है कि IHC को खुद अपने सत्र के लिए पैसे का इंतजाम करना चाहिए। उनके मुताबिक, यूनिवर्सिटी सिर्फ जगह (वेन्यू) ही उपलब्ध कराएगी, बस इतना ही।

इतना ही नहीं, उन्होंने स्थानीय सचिव (Local Secretary) नियुक्त करने से भी मना कर दिया है। उनका तर्क है कि यूनिवर्सिटी में स्थायी स्टाफ कम है, और जो लोग हैं, उनके ऊपर पहले से ही काम का बोझ है। ऐसे में करीब एक हजार प्रतिनिधियों वाले इस सत्र को व्यवस्थित करने के लिए वहाँ कोई स्थानीय व्यवस्था या मशीनरी ही नहीं बन पाएगी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह अंतिम रुख उन्होंने हमें करीब चार महीने बाद बताया। इस दौरान हमने बार-बार पत्र, संदेश और अनुरोध भेजे, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया। हम तो इसी भरोसे पर आगे बढ़ रहे थे कि यूनिवर्सिटी अपनी पुरानी बात पर कायम है और सत्र की मेज़बानी करेगी।

जब हमने कुलपति जी से सीधे पूछा कि अगर यूनिवर्सिटी यह जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी या उठाना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने चार महीने तक मामला क्यों टाला रखा, तो उनका जवाब काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहली बार हामी भरी थी, तो उन्हें लगा कि IHC का सत्र बाकी आम अकादमिक कॉन्फ्रेंस की तरह है, जिनमें 100-150 लोग आते हैं और अपना खर्च खुद उठा लेते हैं। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि IHC सत्र उससे बिल्कुल अलग है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा संगठनात्मक और आर्थिक मदद चाहिए होती है। दुर्भाग्य से, यह गलतफहमी उन्होंने हमें कभी नहीं बताई, जबकि हमने कई महीनों तक लगातार कोशिश की कि हम उन्हें इन्हीं ज़रूरतों के बारे में स्पष्ट कर सकें। अगर यूनिवर्सिटी ने शुरुआत में ही कह दिया होता कि वे आर्थिक मदद नहीं माँगेगे, स्थानीय सचिव नियुक्त नहीं करेंगे, या आयोजन की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो हमारे पास कोई दूसरी जगह ढूँढने के लिए पर्याप्त समय होता।

इसका नतीजा यह हुआ कि अब दिसंबर सत्र में मुश्किल से चार महीने बचे हैं, और भारतीय इतिहास कांग्रेस अपनी कोई गलती न होने के बावजूद बहुत मुश्किल स्थिति में आ गई है। इसलिए हमारे पास डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के साथ हुए इस प्रस्तावित इंतजाम से पीछे हटने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अब हमें आने वाले सत्र के लिए किसी दूसरी जगह की तलाश तुरंत शुरू करनी होगी।